हमारी बात

पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र संघ ने 75 देशों के राष्ट्रपतियों या प्रधान मंत्रियों का एक महासम्मेलन न्यूयार्क (अमेरिका) में आयोजित किया। सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था—'बच्चों के अधिकार'। आज भी करोड़ों बच्चे अकाल मौत से जूझते हैं और रोटी मुहैया करने में बचपन बिताते हैं। आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में हर दिन 40 हजार बच्चे ऐसी बीमारियों से मरते हैं जिनका इलाज है और जिनसे बच्चों की रक्षा की जा सकती है।

इस महासम्मेलन में मोटे रूप से चर्चा के विषय थे—बच्चों को बीमारियों और मरने से बचाना, स्वस्थ शारीरिक व मानसिक विकास के लिए खेल कूद और शिक्षा के अवसर देना, बच्चों का शोषण रोकना और उन्हें स्वस्थ नागरिक बनाने के लिए समुचित अधिकार देना।

एक सवाल हमारे मन में बार-बार उठता है—क्या हम अपने स्तर पर बच्चों के अधिकारों की रक्षा करते हैं? क्या हम उन्हें वह सब दे रहे हैं जो उनको मिलना चाहिए? पढ़ाई-लिखाई और स्वास्थ्य रक्षा को ही लें। हमने पाया कि बहुत से बच्चों, विशेषकर लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता। न ही बीमारियों से बचने के लिए टीके लगवाने पर ध्यान दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्या इसके लिए हम सब जिम्मेदार नहीं हैं? क्या इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है? क्या सामाजिक ढांचा इसके लिए जिम्मेदार है? हम आपके विचार जानना चाहते हैं। आप खुलकर अपने विचार हमें लिखें। आपके विचारों और सुझावों को हम 'सबला' के अगले अंक में छापेंगे। दो सबसे अच्छे पत्रों को इनाम दिया जाएगा।

पिछले कुछ दिनों से हमें यह महसूस हो रहा है कि 'हमारी बात' एकतरफा हो रही है। हम ही कहते चले जा रहे हैं। आप चुप हैं। हम आपकी बात भी सुनना चाहते हैं। आप अपने जीवन के अनुभव, अपने आसपास होने वाली घटनाओं, रूढ़ियों, रीति-रिवाजों आदि किसी भी विषय पर लिखें।

हम आपकी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। न सिर्फ आपके और अपने बीच, बल्कि 'सबला' के सभी पाठकों के बीच एक संबंध बनाना चाहते हैं। आशा है आप जल्दी ही हमें लिखेंगी।

सुहास कुमार